(b) whether the Tobaco Board has extended any financial assistance to the affected farmers; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) No, Sir. Tobacco Board has not proposed for any financial assistance to nursery growers because most of the nursery area has been raised by commercial nurserymen who are not registered with the Board.

Abolition of Child Labour by 2000 A.D.

1377. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have intimated all the State Governments that the child labour be abolished by 2000 A.D.

(b) if so, the reaction of the States thereto;

(c) whether it is also a fact that some State Governments have drawn schemes in this regard; if so, the names of these States; and

(d) what measures are being taken to ensure abolition of child labour in the country by the stipulated period?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (c) It is proposed to divert 20 lakh children working in hazardous occupations from work into education in a phased manner as under:—

1995-96	2.00 lakh
1996-97	4.00 lakh
1997-98	6.00 lakh
1998-99	6.00 lakh
1999-2000	2.00 lakh

During the current financial year, 63 additional projects under the National Child Labour Project Scheme have been sanctioned in addition to the 12 on-going ones. In all, around 1,36,000 children in 11 States namely, A.P., M.P. Orissa, West Bengal, Bihar, U.P. Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu are being covered under the projects. For conducting surveys for identification of child labour engaged in hazardous occupations in different parts of the country, 123 districts have been given financial assistance during the current finanical year.

(d) Measures taken by Government to eliminate child labour, *inter alia*, include;

(i) Consultation with State Labour Ministers in the Eastern, Southern, Western and Northern regions on tackling the child labour problem effectively.

(ii) Constitution of National Authority on Elimination of Child Labour on 26th September, 1994 under the Chairmanship of Union Labour Minister.

(iii) Issue of a detailed Circular on "Identification, Release and Rehabilitation of Child Labour" to all the State Governments for necessary action.

(iv) Focussing of poverty alleviation and income generation programmes of the Government on the families of child labour with a view to economically strengthening them and encouraging them to send their children to school instead to work.

(v) Organisation of a Workshop for Collectors from the most child labour endemic districts in the country.

(vi) Financial assistance to 133 districts in the country for district level awarencess generation activities.

निर्माणाधीन विकास परियोजनाएं

1378. **श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कई विकास योजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और कुल कितनी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार ने कोई विशेष उपाय प्रस्तावित किए थे; और

(घ) यदि हां, तो वे उपाय क्या थे और उपर्युक्त वर्षों में विभागों से संबंधित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनमें से कितने प्रतिशत परियोजनाएं अभी पूरी की जानी है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) तथा (ख) जी हां, 30-6-1995 तक 20 करोड़ रुपए तथा अधिक लागत वाली 383 केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं निर्माणाधीन थीं तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के प्रबोधन पर थीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्माणाधीन परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:—

विवरण	31 मार्च तक		
	1992-93	1993-94	1994-95
(i) कुल परियोजनाओं की संख्या—	352	371	370
(ii) अद्यतन अनुसूची के संदर्भ में समय वृद्धि वाली परियोजनाओं की संख्या	187	200	214
(iii) अद्यतन अनुसूची के सन्दर्भ में लागत वृद्धि वाली परियोजनाओं की संख्या	174	144	146
(iv) अद्यतन अनुसूची के सन्दर्भ में समय पर चल रही परियोजनाओं की संख्या	143	151	132
(v) समय से आगे चल रही परियोजनाओं की संख्या	1	7	6

(ग) और (घ) जी हां, कार्यान्वयन के दौरान परियोजनाओं को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम प्रत्येक परियोजना के लिए समय-समय पर भिन्न होते हैं। फिर भी, कार्यान्वयन में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए सामान्य रूप से जो उपाय सरकार द्वारा किए जाते हैं, वे संलग्न विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिए)। पूर्ण न हो सकने वाली परियोजनाओं का प्रतिशत 1992-93 में 46% रहा, 1993-94 में 53% रहा, 1994-95 में 68% रहा था 1995-96 (जून 1995 तक) 62% रहा।

विवरण

वास्तविक अनुमानों की तैयारी तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुप्रवाही बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

1. उचित तैयारी, पर्यावरणीय एवं अन्य स्वीकृतियों को सुनिश्चित करने के लिए द्वि-स्तरीय परियोजना अनुमोदन एवं स्तर 11 पर कार्यान्वयन के अंतिम अनुमोदन से पहले स्तर पर अधिसंरचनात्मक आयोजन।
2. संशोधित लागत अनुमानों के अनुमोदन की सरलीकृत प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत उद्यमों की सीमा से परे कारणों के कारण लागत वृद्धि मूल निर्माण अवधि को योजना आयोग के परामर्श से प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा स्वीकृत किया जाना है। उपरोक्त कारणों के अलावा अन्य कारणों से अनुमोदित लागत से 5% से अधिक के संशोधित लागत को सार्वजनिक निवेश बोर्ड / मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत होना है।
3. विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं का गहन प्रबोधन: इससे प्रबोधन अभिकरणों को अवरोधों की पहचान करने तथा सुधारात्मक उपाय करने में प्रबंधन को सहायता करने में सहूलियत होती है।
4. परियोजना प्राधिकरणों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों के द्वारा प्रगति की सूक्ष्म आलोचनात्मक समीक्षा।
5. संविदा पैकेजों के तीव्र फैसले, भूमि अधिग्रहण

एवं अन्य समस्याओं के निदान के लिए कार्य दल/उच्चाधिकार समितियों का गठन।

6. कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों तथा परियोजना प्राधिकारों द्वारा राज्य सरकारों, उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं तथा अन्य संबंधित अभिकरणों के साथ विलम्ब को कम करने के लिए निकट से अनुवर्ती कार्रवाई।

7. अन्तर मंत्रालयीय समन्वय एवं परस्पर विचार-विमर्श।

8. वास्तविक परियोजना कार्यान्वयन योजना को तैयार करने पर बल।

9. अवरोधों का सामना करने वाली विशिष्ट परियोजनाओं का सचिवों की समिति के द्वारा समीक्षा।

Buffer Stock of Foodgrain with FCI

1379. SHRI PRAMOD MAHAJAN:
SHRI VIREN J. SHAH:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) what is the present position regarding buffer foodgrain stock with the Food Corporation of India as against the last year;

(b) whether the FCI has been facing storage problems for foodgrain stocks and if so, what are the details in this regard;

(c) how Government propose to meet the situation;

(d) what has been the extent of loss during each of the last three years on account of lack of storage facilities and for other reasons;

(e) whether there is any proposal for the procurement of plastic containers for storage purposes and if so, the details thereof; and

(f) whether Government propose to export foodgrains including wheat and rice during the current year and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) The stocks of foodgrains with Food Corporation of India as on 1.11.1995 and 1.11.1994 were as follows:—

(in Million Tonnes)

	As on 1.11.95(P)	As on 1.11.94(P)
Wheat	6.90	8.21
Rice	11.64	12.83
TOTAL:	18.54	21.04

(P) Provisional

(b) and (c) No. Sir. At macro level the existing storage capacity is adequate to store the available stocks. However, difficulties do arise in the heavy procurement areas. In order to take care of any defficiency at local levels, the field officers of Food Corporation of India have been delegated with powers for hiring additional storage capacity. During the 8th Five Year Plan (1992—97) Food Corporation of India has been given a target of constructing an additional capacity of 6 lakh tonnes out of which it has already constructed 3.24 lakh tonnes so far.

(d) There has been no report of any damage to foodgrains due to lack of storage facilities. However, the quantities of foodgrains transferred from sound: to damaged due to other natural causes such as floods, unprecedented rains, cyclone, multiple handling, transportation etc, during the past three years (1991-92 to 1993-94) are as follows:—

Years	(Quantity '000 MT)
1991-92	19.87
1992-93	9.81
1993-94	45.79

(e) M/s. Vacuum Process Storage Co. Ltd., Ireland had given a proposal for introduction of VPS System in India. In